वार्षिक प्रतिवेदन 2016–17

Annual Report 2016-17

ARAVALI

Association for Rural Advancement through Voluntary Action and Local Involvement
Patel Bhawan, HCM-RIPA (OTS), Jawahar Lal Nehru Marg,
Jaipur – 302017
Telefax: 91-141-2701941, 2710556,
Website: www.aravali.org.in

अरावली

(एशोसिएशन फॉर रूरल एडवांसमेंट थ्रू वॉलन्टरी एक्शन एण्ड लोकल इनवॉल्वमेंट)

स्थापना का उद्देश्य :–

अरावली की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1994 में बजटीय भाषण के तहत् सरकार और गैर सरकारी (स्वैच्छिक संगठनों) के बीच साझेदारी को सशक्त करने एवं राज्य में सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु की गई।

कार्यव्यवस्था :–

अरावली का पंजीकरण 23 जुलाई 1994 को ग्रामीण विकास विभाग द्वाराकियागया। वर्तमान में अरावली का प्रशासनिक विभाग ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग है। अरावली के अध्यक्ष माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार हैं। संस्था की कार्यकारिणी समिति, शासकीय परिषद एवं साधारण सभा में राजस्थान सरकार के वित्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, आयोजना, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कृषि, वन एवं पर्यावरण एवं शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भी पदेन सदस्य हैं। अरावली की साधारण सभा में राजस्थान सरकार के पदाधिकारियां के अतिरिक्त गैर सरकारी संगठनों के सदस्य भी पदेन सदस्यों के रूप में शामिल हैं। अरावली की सोच है कि राज्य में समुदायों के चहुँमुखी और व्यापक विकास के लिए ऐसे साझे प्रयासों एवं अभिगमों की आवश्यकता है जो किसी एक ही संस्था या प्रणाली द्वारा संभव नहीं है। विकास कार्य का लाभ सभी लोगों, विशेषकर गरीब एवं वंचित लोगों तक पहुंचे, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि विकास के क्षेत्र में कार्यरत सभी व्यक्ति एवं संस्थाऐं परस्पर साझेदारी से कार्य करें। इस संदर्भ में अरावली का यह ध्येय है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में आवश्यकतानुसार, पर्याप्त संख्या में प्रभावी स्वैच्छिक संस्थाएं हो, जो पिछड़े व वंचित

समुदाय के साथ व उनके लिए जमीनी स्तर पर कार्य करें। साथ ही, अरावली ऐसे अनुकूल वातावरण का निर्माण करना चाहती है जिसमें सरकार एवं स्वैच्छिक संस्थाऐं अपनी–अपनी शक्तियों व अनुभवों को जोड़कर, विकास कार्य में साझेदार बन सकें। राजस्थान के विकास में अरावली ने अपना वृहद योगदान दिया है, वह पिछले 19 वर्षों से ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन तथा गरीब परिवारों को सरकारी कार्यक्रमों से जुड़ाव आदि के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। अरावली ने राज्य में कुल 150 से अधिक गैर सरकारी संगठनों का सशक्तिकरण कर उपरोक्त क्षेत्रों में योगदान दिया है। इस कार्य में अरावली को विभिन्न दानदाता संगठनों ने अपना आर्थिक सहयोग दिया है जिनमें प्रमुख है : केन्द्र एवं राजस्थान सरकार, आगा खॉ फाउण्डेशन, सर रतन टाटा ट्रस्ट, यूनीसेफ, यू.एन.डी.पी., पॉल हेमलिन फाउण्डेशन, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आदि।

अरावली के प्रमुख उद्देश्य हैं :–

1. सरकार व गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
2. राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं एवं सरकारी अधिकारियों का क्षमतावर्धन विभिन्न प्रशिक्षणों एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से करना।
3. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, परियोजनाओं का मूल्यांकन व प्रबोधन कार्य करना।
4. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु उचित प्रोद्योगिकी का अनुसंधान कर पहचान करना व स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से पायलट करना।
5. स्वैच्छिक प्रयासों और स्थानीय भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास हेतु समग्र रणनीति व दृष्टिकोण को मजबूत करना।
6. ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हुई प्रभावी प्रयासों का दस्तावेजीकरण करना व राज्य के प्रमुख स्टेक होल्डर के समक्ष रखना।

विशेषता–

अरावली न ` कुल 150 से अधिक स्वंयसवे ी संगठनों की क्षमतावर्धन किए हैं जो राजस्थान के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहें हैं। अरावली ने पिछले 19 वर्षों से ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन के तहत् गरीब परिवारों की आजीविका संवर्द्धन व सरकार के कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ाव का कार्य, कृषि, जल संसाधन, स्वास्थ्य परियोजना, आदि के क्षेत्र में कार्य किए हैं। राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों में स्वंयसेवी संगठनों के जुड़ाव हेतु कार्यरत है।

अरावली के प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं :–

1. **प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम** – प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम आयोजित करना। राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं का क्षमतावर्धन व प्रशिक्षण कार्य। विभिन्न विषयों पर जैसे ग्रामीण विकास, जल संसाधन, कृषि एवं पशुपालन प्रबंधन व विकास, स्वास्थ्य, गरीबी आंकलन, आजीविका संवर्धन, जल एवं स्वच्छता आदि पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करना।

2. **मानवीय एवं संस्थागत विकास कार्यक्रम** –

    - विभिन्न विषयों पर कायर्क र्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
    - सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के लोगों में प्रबन्धन कौशल बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।
    - सूचना का आदान प्रदान व परस्पर ज्ञान बांटना।
    - प्रबन्धन, क्रियाकलापों व शोध के लिए दक्ष सहायता उपलब्ध करवाना।
    - स्वैच्छिक संगठनों एवं विकास कार्य से जुड़े सस्ं थाओं के मध्य सूचनाओं को पहुंचाने हेतु 'अरावली विकास फीचर सेवा' का संकलन कर तकरीबन 350 से अधिक संस्थाओं तक प्रेषित करना।

3. **अनुसंधान एवं ज्ञान (नॉलेज बिल्डिंग)** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों हेतु आजीविका संवर्धन करना व सरकारी योजनाओं के साथ जुड़ाव, नवाचार प्रयासों को प्रोत्साहित कर दस्तावेजीकरण करना।

- विभिन्न विकास के कार्यक्रमों का मूल्यांकन, प्रबोधन एवं योजनाओं के प्रभावी आंकलन कार्य करना। अरावली ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार व अन्य संगठनों हेतु आंकलन कार्य किए हैं।

- अरावली ने ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर शोध एवं अध्ययन कार्य किए हैं विशेषकर वर्षा आधारित कृषि, जलग्रहण विकास कायर्क्र म, पशुपालन, वानिकी, समुदाय आधारित लघुवित्त कार्यक्रम, तथा राज्य में आजीविका के क्षेत्र में शोध कार्य आदि।

- अरावली ने कृषि विभाग हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 8 जिलों के 54 ब्लाक एवं 54 ग्राम पंचायतों हेतु विकेन्द्रिकृत नियोजन कार्य किए हैं। तथा राज्य के सभी जिलों के कृषि अधिकारियों हेतु नियोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम किए हैं।

- अरावली ने राजस्थान में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों का डेटा बेस प्रबंधन कार्य किए

  हैं।

4. **सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों के मध्य साझेदारी को सशक्त करना–**

- राज्य एवं जिले स्तर पर इंटरफेस कार्यशाला (संवाद बैठक) का आयोजन करना।

- स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक (प्री–बजट संवाद बैठक) माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में आयोजित करना।

- राज्य में कई विषयों को लेकर राज्य स्तरीय फोरम का गठन एवं संचालन करना।

- राज्य में गैर सरकारी संगठनों का आंकलन करना।

वर्तमान में अरावली निम्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है:—

1. **राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्द्धात्मक परियोजना :—**

यह परियोजना जो कि विश्व बैंक की सहायता से विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में लगभग 10—31 हजार हैक्टर के क्लस्टर्स (गांवों का समूह) का चयन कर कुल 17 क्लस्टर्स में 2.75 लाख हैक्टर क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में उत्पादकता को विकसित किया जायेगा। अरावली इस परियोजना में पार्टनर एजेन्सी के तौर पर विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन कार्यक्रम आयोजित करने का कार्य कर रही है। क्षमतावर्द्धन व प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत् अरावली द्वारा 17 क्लस्टर्स में 3500 से अधिक किसानों हेतु लगभग 90 जागरूकता कार्यक्रम क्लस्टर्स एवं ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए गए हैं।

- अरावली द्वारा पशुपालन विभाग हेतु 100 से अधिक लेडी लिंक वर्कर का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर विभिन्न क्लस्टरों में पशुपालन संवर्द्धन (बकरी पालन) हेतु कार्य किया है।

- अरावली ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें प्रमुख हैं – वाटर बजटिंग, सामुदायिक जागरूकता, प्रशिक्षण आवश्यकता आंकलन, एग्री बिजनेश प्रमोन फैसेलिटी इत्यादि।

- सरकारी अधिकारियों (कृषि एवं पशुपालन विभाग) का आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी 17 क्लस्टर्स हेतु आयोजित किए हैं। साथ ही परियोजना सम्वयकों व अन्य अधिकारियों हेतु भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

- आर.ए.सी.पी. परियोजना का हिन्दी में विभिन्न प्रकार के कृषि, पशुपालन, जलग्रहण, बागवानी, भूजल व जल संसाधन संबंधित पोस्टर्स भी प्रकाशित किये गये हैं।

2. **राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) –** अरावली द्वारा राजीविका के साथ हुए एमओयू एवं कंवरजेन्स प्लान 2016–17 के तहत् 11 जिले (उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपूर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, अलवर और दौसा) के 24 ब्लाकों में लगभग 25000 स्वंय सहायता समूहों के सदस्यों का महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत् अपना खेत अपना काम में आवेदन मंजूरी हेतु कार्य किया है। इसके तहत् लगभग 1500 कार्य शुरू हो चुके हैं।

3. **ग्रामीण विकास विभाग (प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण) –** अरावली द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के तहत् राज्य एव ं जिले स्तर पर अधिकारियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्वंयसेवी संगठनों हेतु 15 से अधिक प्रशिक्षण एवं आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया है जिसके तहत् लगभग 500 कार्मिकों का प्रशिक्षित किया गया है।

   अरावली द्वारा आवास योजनान्तर्गत टैग ऑफिसर हेतु राज्य के 10 जिलों (उदयपुर, जोधपुर, जालोर, प्रतापगढ़, पाली, करौली, डूंगरपूर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा) में 284 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर लगभग 12000 टैग ऑफिसर प्रशिक्षित किए हैं।

4. **स्वैच्छिक संगठन, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व राज्य स्तरीय संवाद बैठक–** अरावली द्वारा ग्रामीण विकास विभाग को सहयोग करते हुए स्वैच्छिक संगठनों, सिविल सोसायटी एवं उपभोक्ता मंच के साथ बजट पूर्व संवाद बैठक माननीय मुख्यमंत्री महोदया की अध्यक्षता में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

5. **प्राकृतिक स्टोन क्षेत्र में बाल अधिकार संरक्षण को प्रोत्साहित करना–**

   - यूनीसेफ, जयपुर के सहयोग से बूंदी कोटा क्षेत्र में खनन् क्षेत्रों में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से बाल अधिकार संरक्षण हेतु कार्य कर रही है।

   - साथ ही 200 खनन मजदूर परिवारों को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं से जुड़ाव का कार्य कर रही है।

- यूनीसेफ के सहयोग से कोटा में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन खनन क्षेत्र में बाल अधिकार संरक्षण एवं उनके परिवारों के आजीविका संवर्द्धन हेतु कार्य किया है, जिसमें राज्य भर से 100 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

- इस हेतु राज्य स्तर पर एक साझा प्रयासों के अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय फोरम भी स्थापित किया गया है जिनकी नियमित तौर पर बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

- इस हेतु राज्य स्तर पर एक साझा प्रयासों के अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय फोरम भी स्थापित किया गया है जिनमें स्वंयसेवी संगठन, ट्रेड यूनियन, रिसर्च एजेन्सी एवं यूनीसेफ के प्रतिनिधि जुड़कर नियमित बैठकें आयोजित कर खनन मजदूरों के परिवारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, आजीविका संवर्द्धन आदि पर कार्य कर रही है।

नवीनतम योजना– अरावली द्वारा प्रतिवर्ष 50 स्वंयसेवी संगठनों एवं राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कार्मिकों हेतु प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्धन कार्यक्रम करने हेतु स्वंय का प्रशिक्षण संदर्भ केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है।